



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 16, 2016/भाद्र 25, 1938

No. 297]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2016/BHADRA 25, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2016

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

विषय : कोरिया गणराज्य, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पोलीबुटाडीन रबड़ या पीबीआर" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क संबंधी जांच की शुरूआत।

संख्या 14/40/2016 –डीजीएडी.—मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज (जिसे आगे 'याचिकाकर्ता' या 'आवेदक' कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) के अनुसार कोरिया गणराज्य, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और सिंगापुर (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पोलीबुटाडीन रबड़ या बुटाडीन रबड़" (जिसे आगे पीबीआर या संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क सऊदी अरब के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नार्मल बुटानोल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन (जिसे याचिका भी कहा गया है) प्रस्तुत की है।

1. और यतः प्राधिकारी यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए कोरिया गणराज्य, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और सिंगापुर के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं। प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कोरिया गणराज्य, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ईरान

और सिंगापुर के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

2. यह आवेदन मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे आगे घरेलू उद्योग या आवेदक कहा गया है) द्वारा भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादक के रूप में दायर किया गया है। याचिकाकर्ता कंपनी देश में संबद्ध वस्तु की एकमात्र उत्पादक है याचिकाकर्ता ने न तो विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही वे विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित है। अतः प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि आवेदक संबंधित नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अधीन 'योग्यता' संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है।

विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद 'पालीबुटाडीन रबड़' या 'बुटाडीन रबड़' जिसे बाजार शब्दावली में 'पीबीआर' के रूप में भी जाना जाता है, है। पालीबुटाडीन एक कृत्रिम रबड़ है जो मोनोमर 1.3 बुटाडीन के पालीमराइजेशन से निर्मित पालिमेर है। पालीबुटाडीन में वियर का उच्च प्रतिरोध होता है और इसका प्रयोग विशेष रूप से टायरों जो भारत में उत्पादित पीबीआर के लगभग 70%-80% की खपत करते हैं, के विनिर्माण में किया जाता है। अन्य 20 प्रतिशत का प्रयोग पालीस्टाइरीन और एक्रीलोनाइट्राइल बुटाडीन स्टीरीन (एबीएस) जैसे प्लास्टिकों की यांत्रिक शक्ति को बढ़ाने के लिए एडिटिव के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग गोल्फ बालों, विभिन्न इलास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण में और इलेक्ट्रॉनिक सहायक सामग्री को कोट या ढकने के लिए भी किया जाता है जो उच्च विद्युत प्रतिरोध प्रदान करता है।

4. 'बीआर' या 'पीबीआर' को ग्रेडों और गुणवत्ता के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। पीबीआर की पाँच विभिन्न श्रेणियाँ – टिटैनियम, लीथियम, कोबाल्ट, निकल और नियोडिमियम होती हैं। पीबीआर का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण पालीमराइजेशन प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त उत्प्रेरक के प्रकार पर आधारित होता है। प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक के आधार पर पालीमराइजेशन के परिणामस्वरूप शृंखला की विशिष्ट नियमितता (सिस-मात्रा द्वारा मापित) या शृंखला की लीनियरटी होती है। प्रयुक्त उत्प्रेरक और उनकी संगत सिस मात्रा निकल ग्रेड, कोबाल्ट ग्रेड और नियोडिमियम ग्रेड होती है। याचिकाकर्ता उत्पाद के केवल कोबाल्ट, निकल और नियोडिमियम ग्रेडों का उत्पादन कर रहा है। याचिकाकर्ता ने बताया है कि अन्य दो ग्रेड टिटैनियम, लीथियम का प्रौद्योगिकी के अभाव में याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता है। चूंकि याचिकाकर्ता के पास टिटैनियम और लीथियम ग्रेडों के उत्पादन की प्रौद्योगिकी नहीं है इसलिए इन दो ग्रेडों का विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है। इस प्रकार विचाराधीन उत्पाद पीबीआर के टिटैनियम, लीथियम ग्रेडों को छोड़कर 'पालीबुटाडीन रबड़' है।

5. 1.3-बुटाडीन एक कार्बनिक यौगिक है जो एक सरल कानजुगेटेड डाइन हाइड्रोकार्बन है (डाइन में दो कार्बन-कार्बन डबल बांड होते हैं)। पालीबुटाडीन काफी लंबी पालीमेर अणु चेन बनाने के लिए 1.3-बुटाडीन मोनोमरों को जोड़कर बनता है। पालीमेर चेन के जुड़ाव के अनुसार, बुटाडीन को तीन विभिन्न तरीकों अर्थात् सिस, ट्रांस और विनाइल में पालीमराइज किया जा सकता है।

6. विचाराधीन उत्पाद को मापने की विहित इकाई किलोग्राम/एमटी है और इसे सार्वभौमिक रूप से ऐसे ही बेचा जाता है। संबद्ध वस्तु को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 40 के अंतर्गत उपशीर्ष 40022000 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और प्रस्तावित जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

7. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित की गई वस्तु भारत में संबद्ध देश से आयात की गई संबद्ध वस्तु, के समान वस्तुएं हैं। संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं के अनुसार तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। जाँच के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु है। अतः वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

संबद्ध देश

8. वर्तमान जाँच में शामिल देश कोरिया गणराज्य, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और सिंगापुर हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु को ईरान से यूएई के रास्ते यानांतरित और भारत में प्रविष्ट किया जा रहा है। यूएई संबद्ध वस्तु का उत्पादक नहीं है परंतु यूएई से संबद्ध वस्तु की काफी मात्रा का आयात किया जा रहा है। संबद्ध वस्तु का ईरान में उत्पादन किया जाता है और यूएई के रास्ते भारत में प्रेषण किया जा रहा है।

सामान्य मूल्य

9. याचिकाकर्ता ने परिकलित सामान्य मूल्य पर विचार करते हुए कोरिया गणराज्य, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और सिंगापुर में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा किया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उत्पादन की कुल लागत का 65 -70% हिस्सा कच्ची सामग्री होती है। इसके अलावा बुटाडीन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय रूप से सुस्थापित है। याचिकाकर्ता ने व्यापार पत्रिकाओं, खपत कारक, घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत और लाभ के अनुसार बुटाडीन की कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है।

10. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के दावे की जाँच की है और यह पाया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

निर्यात कीमत

11. याचिकाकर्ता ने आईबीआईएस के आकड़ों के आधार पर विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत का दावा किया है। कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय भाड़े, पत्तन व्यय और बैंक प्रभार के लिए समायोजनों का दावा किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

पाटन मार्जिन

12. इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया सिद्ध होता है कि प्रत्येक संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु को उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया जा रहा है, इस प्रकार भारतीय बाजार में पाटन हो रहा है। सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जो संबद्ध देशों के संबंध में भारी पाटन मार्जिन दर्शाती है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

13. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और संबद्ध देशों से कथित पाटन के परिणामस्वरूप लाभों, नियोजित पूंजी पर आय, नकद लाभ में गिरावट और कीमत संबंधी मापदंडों में गिरावट के रूप में क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने प्रतिकूल कीमत प्रभावों का भी दावा किया है जो कीमत ह्रास और कम कीमत पर बिक्री से साक्ष्यांकित है। प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग को हो रही क्षति और यह क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण होने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

जांच अवधि

14. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक है। तथापि क्षति जाँच के प्रयोजनार्थ इस अवधि में पिछले तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013, अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014, अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 और जांच की अवधि (पीओआई) शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

15. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच से संगत अनुरोध कर सकता है और सूचना निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत की जा सकती है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,****वाणिज्य विभाग****पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय****चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग,****नई दिल्ली- 110001****समय-सीमा**

16. इस जाँच से संबंधित कोई सूचना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

17. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत के बारे में घरेलू उद्योग की याचिका पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

18. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध 'गोपनीय' होने का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि); और (ख) अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए।

19. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ और अगोपनीय पाठ की दो-दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
20. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
21. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना , जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है ,पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध /रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि , आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
22. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
23. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
24. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

25. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

26. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)**

New Delhi, the 16th September, 2016

INITIATION NOTIFICATION

Subject: Initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of “Polybutadiene Rubber or PBR” originating in or exported from Korea PR, Russia, South Africa, Iran and Singapore.

F. No.14/40/2016 DGAD.—M/s Reliance Industries Limited (hereinafter referred to as ‘petitioner’ or “the applicant”) has filed an application (also referred to as petition) before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of anti dumping investigation concerning imports of “Polybutadiene Rubber or Butadiene Rubber” (hereinafter referred to as PBR or subject goods or product under consideration) originating in or exported from Korea PR, Russia, South Africa, Iran and Singapore (hereinafter referred to as subject countries).

1. AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from Korea PR, Russia, South Africa, Iran and Singapore, ‘injury’ to the domestic industry and causal link between the dumping and ‘injury’ exists to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping of the product under consideration originating in or exported from Korea PR, Russia, South Africa, Iran and Singapore, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the ‘injury’ to the domestic industry.

Domestic Industry & Standing

2. The petition has been filed by M/s Reliance Industries Limited (hereinafter referred to as the domestic industry or the applicant), as producers of the subject goods in India. Petitioner Company is the sole producer of the subject goods. Petitioner has neither imported the product under consideration, nor are they related to an importer or exporter of the product under consideration. The Authority, therefore, determines that the applicants constitute domestic industry within the meaning of the Rule 2 (b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

Product under consideration

3. The product under consideration is "Polybutadiene Rubber" or "Butadiene Rubber" also known as “PBR” in the market parlance. Polybutadiene is a synthetic rubber that is a polymer formed from the polymerization of the monomer 1,3-butadiene. Polybutadiene has a high resistance to wear and is used especially in the manufacture of tyres, which consumes about 70%-80% of the PBR produced in India. Another 20% is used as an additive to improve the mechanical strength of plastics such as polystyrene and acrylonitrile butadiene styrene (ABS). It is also used to manufacture golf balls, various elastic objects and to coat or encapsulate electronic assemblies, offering high electrical resistivity.
4. “BR” or “PBR” can be classified in terms of grades and quality. There are five different categories of PBR - Titanium, Lithium, Cobalt, Nickel and Neodymium. This classification of PBR into different categories is based on the type of catalyst used during the polymerization process. Based on the catalyst used in the process, the polymerization will result in the stereo-regularity of the chain (measured by the cis-content) or linearity of the chain. Generally grades of BR are differentiated based on their cis-content. The catalyst used and their corresponding cis-contents are Nickel Grade, Cobalt Grade and Neodymium Grade. The petitioner is producing only Cobalt, Nickel and Neodymium grades of the product. Petitioner has submitted that the other two grades Titanium, Lithium are not produced by the petitioner because of lack of technology. Since the petitioner does not have the technology to produce Titanium and Lithium grades, therefore, these two grades have been excluded from the scope of product under consideration. Thus, product under consideration is "Polybutadiene Rubber" excluding Titanium, Lithium grades of PBR.

5. 1,3-Butadiene is an organic compound that is a simple conjugated diene hydrocarbon (dienes have two carbon-carbon double bonds). Polybutadiene forms by linking many 1,3-butadiene monomers to make a much longer polymer chain molecule. In terms of the connectivity of the polymer chain, butadiene can be polymerized in three different ways, called *cis*, *Trans* and *vinyl*.
6. The prescribed unit of measurement for the product under consideration is kilograms/MT and it is universally sold in the same. Subject goods are classified under Chapter 40 of Customs Tariff Act, 1975 under the subheading 40022000. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the proposed investigations.

Like Articles

7. The petitioner has claimed that the product manufactured by the domestic industry and the subject goods imported into India from the subject countries are like articles within the meaning of the Anti-dumping Rules. There is no known difference between the subject goods imported from the subject countries and that produced by the domestic industry. The subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The consumers can use and are using the two interchangeably and are technically and commercially substitutable. After examination, the Authority concludes that the subject goods produced by the domestic industry are like article to that imported from the subject countries. Therefore, for the purpose of present investigation the subject goods produced by the applicant in India are being treated as like article to the subject goods being imported from subject countries.

Subject Countries

8. The countries involved in the present investigation are Korea PR, Russia, South Africa, Iran and Singapore. Petitioner has claimed that the subject goods are being transshipped from Iran via UAE and entering into India. UAE is not the producer of the subject goods but a considerable quantity of the subject goods are being imported from UAE. The subject goods are produced in Iran and being dispatched to India via UAE.

Normal value

9. The petitioner has claimed determination of normal value of the subject goods in Korea PR, Russia, South Africa, Iran and Singapore by considering the constructed Normal value. Petitioner has claimed that raw material accounts for 65 -70% of total cost of production. Further, price of Butadiene are well established internationally. The petitioner has claimed normal value on the basis of Butadiene price as per trade journals, consumption factor, conversion cost of domestic industry and profit.
10. The Authority has examined the claim of the petitioner and finds that there is sufficient prima facie evidence of normal value of the subject goods in the subject countries.

Export Price

11. The petitioner has claimed export price for product under consideration based on IBIS data. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight, port expenses, and bank charges to arrive at net export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence with regard to the export price claimed by the petitioner.

Dumping Margin

12. There is sufficient evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the export price, prima-facie establishing that the subject goods originating in or exported from each of the subject countries are being exported a price below normal value, thus resulting in dumping of the subject goods in the Indian market. Normal value and export price have been compared at ex-factory level which shows significant dumping margin in respect of subject countries.

Injury and Causal Link

13. The petitioner has claimed that domestic industry has suffered material injury and has furnished evidence regarding injury having taken place as a result of the alleged dumping from subject countries in terms of deterioration in profits, return on capital employed, cash profit and deterioration in price parameters. The petitioner has also claimed adverse price effects as evidenced by price depression and price under selling. The Authority considers that there is sufficient evidence of 'injury' being suffered by the domestic industry and the same is being caused by dumped imports of subject goods from the subject countries.

Period of Investigation

14. The period of investigation for the present investigation is from 1st April, 2015 to 31st March, 2016. However, for the purpose of injury investigation, the period will cover the data of previous three years, i.e. April, 2012 to March, 2013, April, 2013 to March, 2014, April, 2014 to March, 2015 and the Period of Investigation (POI).

Submission of information

15. The known exporters in the subject countries and their Governments through their Embassies in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

**The Designated Authority,
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street
New Delhi - 110001**

Time limit

16. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.
17. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to impose anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of Information on Non-Confidential basis

18. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
19. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

20. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
21. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
22. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
23. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
24. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

25. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

26. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority